भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2560

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- एम.एस.पी. पर खरीद की स्थिति

2560. श्री जय प्रकाशः

श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसानों को हिसार और सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में एम.एस.पी. पर गेहूं, धान, बाजरा और अन्य फसलों के क्रय हेतु पंजीकरण संबंधी समस्याओं, गुणवत्ता मानकों, क्रय नियमों/प्रक्रियात्मक बाधाओं तथा समय पर भुगतान में विलंब जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हिसार और सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में एम.एस.पी. पर खरीद किए गए गेहूं, धान, बाजरा और अन्य फसलों की मात्रा कितनी है और लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है तथा भुगतान की औसत अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्रय प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, अधिक प्रभावी, डिजिटल रूप से समयबद्ध बनाने तथा किसानों के बैंक खातों में सीधे त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई नई प्रणाली लागू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों को प्राप्त होने वाले संभावित लाभ क्या हैं; और

(ङ) किसानों की क्रय नियमों से संबंधित शिकायतों के निवारण तथा क्रय केंद्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): हरियाणा सरकार के अनुसार, वर्ष 2020 से राज्य में अधिसूचित फ़सलों की खरीद ई-खरीद पोर्टल के माध्यम की जा रही है। खरीद की प्रक्रिया सुदृढ़ तथा कार्यक्षम है और सुचारू रूप से चल रही है। खरीद कार्य के दौरान कोई बड़ी तकनीकी समस्या नहीं आई। छोटी-मोटी तकनीकी समस्याएँ हर ऑनलाइन प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं; खरीद कार्य के सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के समर्पित हेल्पडेस्क और तकनीकी सहायता टीमों ने इन समस्याओं को तुरंत ठीक किया।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान हिसार और सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी गई गेहूं, धान, बाजरा और अन्य फसलों की मात्रा तथा इससे लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ग) और (घ): हाल के वर्षों में, खरीद प्रक्रिया को सुदृढ़ करने, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में एमएसपी का सीधा भुगतान सुनिश्चित करने और आधार व भूमि के रिकॉर्ड को राज्यों के खरीद पोर्टलों से एकीकृत करने के लिए डिजिटल पहल शुरू की गई हैं, ताकि एमएसपी खरीद का लाभ सही किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुँच सके। इसके अतिरिक्त, किसानों की खरीद सुविधाओं तक पहुँच बेहतर बनाने के लिए, खरीद एजेंसियों ने राज्य सरकारों के परामर्श से यथा-अपेक्षित सीधे खरीद केंद्रों सहित पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, किसानों को एमएसपी का भुगतान समय पर करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) को कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) उपलब्ध कराई जाती हैं। एमएसपी खरीद की प्रक्रियाओं के बारे में किसानों की जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों और खरीद एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से जागरूकता और प्रचार अभियान चलाए जाते हैं। खरीद प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एफसीआई द्वारा उठाए गए पहलों में बायोमेट्रिक-आधारित खरीद प्रणाली लागू करना और डिजिटाइज़्ड मंडी/खरीद केंद्र के कामकाज को एकीकृत करना शामिल है। साथ ही, खरीद की समय-सारणी, खरीद केंद्रों और खरीद से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की सूचना देने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, सार्वजनिक घोषणाओं और संचार के अन्य माध्यमों से बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जाता है, जिससे किसानों की जानकारी बढ़ती है और खरीद प्रक्रिया तक उनकी पहुंच बेहतर होती है।

वर्ष 2014-2026 (जून 2026 तक) की अवधि के दौरान सम्पूर्ण भारत के लिए खरीद का विवरण और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी की राशि नीचे दी गई है:

	एलएमटी में खरीद	एमएसपी का मूल्य लाख करोड़ में
अखिल भारत	12,819	27.80

(ङ): संचालन समस्याओं का समय पर समाधान करने के लिए संबंधित एजेंसियों के समन्वय से खरीद कार्यों की लगातार निगरानी और समीक्षा की जाती है। हरियाणा राज्य में खरीद से संबंधित किसानों की शिकायतों के समय पर समाधान के लिए, विशेष तकनीकी सहायता टीमों के साथ एक हेल्प डेस्क शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार एक केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) संचालित करती है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो नागरिकों के लिए 24x7 उपलब्ध है, ताकि वे सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर सरकारी अधिकारियों के पास अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।

अनुबंध

वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक हिसार और सोनीपत लोकसभा क्षेत्रों में खरीद का विवरण

हिसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हिसार, जींद और भिवानी जिले शामिल हैं

वर्ष	गेहूं की खरीद)मीट्रिक टन(	लाभान्वित किसानों की संख्या	सरसों की खरीद)मीट्रिक टन(	लाभान्वित किसानों की संख्या	धान की खरीद)मीट्रिक टन(	लाभान्वित किसानों की संख्या	बाजरा की खरीद)मीट्रिक टन(	लाभान्वित किसानों की संख्या
2023-24	5,26,142.30	34,990	71,024.75	26,062	99,875.99	8,918	14,327.35	7,215
2024-25	6,07,472.50	44,155	1,14,600.45	46,626	73,213.20	7,127	21,872.75	10,384
2025-26	6,49,047.80	43,154	76,815.75	27,515	87,448.45	7,764	18,085.85*	5,918

सोनीपत लोकसभा क्षेत्र

वर्ष	गेहूं की खरीद)मीट्रिक टन(	लाभान्वित किसानों की संख्या	सरसों की खरीद)मीट्रिक टन(	लाभान्वित किसानों की संख्या	धान की खरीद)मीट्रिक टन(	लाभान्वित किसानों की संख्या	बाजरा की खरीद)मीट्रिक टन(	लाभान्वित किसानों की संख्या
2023-24	5,28,228.70	31,491	7,087.15	3,609	29,376.25	2,233	1,273.25	649
2024-25	6,46,635.75	37,954	12,247.30	7,108	27,097.25	2,091	2,768.75	1,522
2025-26	6,66,921.90	35,990	6,320.70	3,635	36,848.20	2,812	3,005.50*	1,252

* केएमएस 2025-26 के दौरान, भावान्तर भरपाई योजना के तहत बाजरे की खरीद 575/- प्रति क्विंटल की दर से की गई।

हिसार लोकसभा क्षेत्र में कपास की खरीद

जिला	2023-24		2024-25		2025-26	
	गांठों के रूप में कपास की खरीद	लाभान्वित किसानों की संख्या	गांठों के रूप में कपास की खरीद	लाभान्वित किसानों की संख्या	गांठों के रूप में कपास की खरीद	लाभान्वित किसानों की संख्या
भिवानी	12,874	2,312	14,303	3,130	8,861	2,264
हिसार	13,665	2,331	11,143	2,177	37,096	9,891
जींद	--	--	--	--	1,700	391
कुल	26,539	4,643	25,446	5,307	47,657	12,546

*****